राष्ट्रीय क्रिया परिषद (एनएसी)
NATIONAL ACTION COUNCIL (NAC)
for Establishment of Ministry of Artisan Affairs
Convened by Vanshanugath & Other Artisans Development Foundation (VADF) · Section 8 Company

PRESS RELEASE · FOR IMMEDIATE PUBLICATION

Artisan Leaders from 14 States Converge in Delhi; National Action Council Resolves to Seek a Dedicated Ministry of Artisan Affairs

National Convention of Artisan Leadership adopts four founding resolutions, confirms national and state leadership, and charts a roadmap toward institutional recognition for India's artisan communities

New Delhi, 28 June 2026 —

Artisan leaders, Vishvakarma organizations, traditional and hereditary artisan communities, cooperatives, academicians, former civil servants and policy professionals from fourteen States and Union Territories gathered here today for the National Convention of Artisan Leadership, convened by the National Action Council (NAC) for Establishment of Ministry of Artisan Affairs, with secretariat support from the Vanshanugath & Other Artisans Development Foundation (VADF), a Section 8 Company.

The Convention was called to address what organizers describe as a long-standing governance gap: artisan-related development functions in India are presently distributed across at least nine Ministries and Departments — including Micro, Small and Medium Enterprises, Textiles, Rural Development, Skill Development and Entrepreneurship, Tribal Affairs, Social Justice and Empowerment, Culture, Tourism, and Commerce and Industry — with no single institution carrying comprehensive responsibility for the social, economic and technological advancement of the country's artisan communities.

At the conclusion of the day-long deliberations, the Convention adopted four founding resolutions: a formal recommendation to the Government of India for the establishment of a dedicated Ministry of Artisan Affairs; the expansion and operationalization of the National Action Council together with confirmation of its national and State leadership; the constitution of a National Women Artisans Empowerment Cell; and the adoption, on a provisional six-month basis, of a national operating structure extending from the National Committee through State, District, Town and Village Committees.

Leadership Speaks

> *"This Convention marks the beginning of the next national phase of organized, evidence-based action towards institutional recognition for India's artisan communities. We are not asking for charity — we are asking for the same coordinated policy attention that other strategically important sectors already receive." — Adv. A. Padma Chary Ausala, National President, National Action Council*

> *"India's artisans are not a welfare constituency; they are a productive national asset. A dedicated Ministry would end the fragmentation that has, for decades, left artisan development without a single accountable home in government." — Dr. V. Vishwanathan Achary, National Principal Advisor, National Action Council*

> *"We leave Delhi with a National Roadmap for 2026–29 and a 100-Day Action Plan — State leadership identified, district mapping under way, and a National Participation Database in preparation. This is a movement built on structure, not sentiment." — Prof. Sagar Zilpe, National Secretary, National Action Council*

National Expansion

The Convention confirmed State Chairpersons for Kerala, Punjab, Maharashtra, Uttar Pradesh, Puducherry, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Bihar, Haryana and Delhi, with further States and Union Territories invited to nominate leadership in the weeks ahead. State Chairpersons have been asked to identify District-level leadership and organisational partners within two weeks.

The Road Ahead

The National Secretariat will shortly open a consultation process for eight National Working Groups covering Policy, Legal Affairs, Government Relations, Women, Youth, Technology and Data, Research, and Media. Within 100 days, the Council intends to form a White Paper Committee on the case for a Ministry of Artisan Affairs, prepare a formal Government Engagement Framework, and initiate consultations toward a National Advisory Council comprising retired Secretaries to the Government of India, former civil servants, economists, legal experts and academicians.

Organisers have described the Convention as a constructive, evidence-based and institution-building initiative that is non-political in nature, open to artisan organisations, researchers, policy experts, industry and civil society alike.

About the National Action Council

The National Action Council (NAC) for Establishment of Ministry of Artisan Affairs is a national coordinating platform working toward institutional recognition, policy coordination and evidence-based development for India's artisan communities. It functions under the administrative and legal framework of the Vanshanugat & Other Artisans Development Foundation (VADF), a Section 8 Company.

— समाप्त / ENDS —

Media Contact: National Secretariat, National Action Council | karigar@artisansministry.com | pranaam@artisans.ngo | +91 96079 79893 | www.artisansministry.com

राष्ट्रीय क्रिया परिषद (एनएसी)
NATIONAL ACTION COUNCIL (NAC)
for Establishment of Ministry of Artisan Affairs
Convened by Vanshanugat & Other Artisans Development Foundation (VADF) · Section 8 Company

प्रेस विज्ञप्ति · तत्काल प्रकाशनार्थ

14 राज्यों के कारीगर नेता दिल्ली में एकत्रित; राष्ट्रीय क्रिया परिषद ने कारीगर मामलों के लिए पृथक मंत्रालय की माँग का प्रस्ताव पारित किया

राष्ट्रीय कारीगर नेतृत्व सम्मेलन में चार संस्थापक प्रस्ताव पारित, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेतृत्व की घोषणा, तथा भारत के कारीगर समुदायों की संस्थागत पहचान हेतु रोडमैप प्रस्तुत

नई दिल्ली, 28 जून 2026 —

देश के चौदह राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से कारीगर नेताओं, विश्वकर्मा संगठनों, परंपरागत एवं वंशानुगत कारीगर समुदायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षाविदों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों तथा नीति विशेषज्ञों ने आज यहाँ राष्ट्रीय कारीगर नेतृत्व सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन कारीगर मामलों के मंत्रालय की स्थापना हेतु राष्ट्रीय क्रिया परिषद (एनएसी) द्वारा किया गया, जिसे वंशानुगत एवं अन्य कारीगर विकास फाउंडेशन (वीएडीएफ), एक धारा 8 कंपनी, का सचिवालयीय सहयोग प्राप्त है।

आयोजकों के अनुसार यह सम्मेलन एक दीर्घकालिक शासकीय अंतराल को संबोधित करने हेतु बुलाया गया। वर्तमान में कारीगर विकास से संबंधित कार्य कम से कम नौ मंत्रालयों एवं विभागों में विभाजित रूप से संचालित होते हैं — जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वस्त्र, ग्रामीण विकास, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, संस्कृति, पर्यटन तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सम्मिलित हैं — जबकि देश के कारीगर समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी विकास की समग्र जिम्मेदारी किसी एक संस्था के पास नहीं है।

दिन-भर चली विचार-विमर्श प्रक्रिया के समापन पर सम्मेलन में चार संस्थापक प्रस्ताव पारित किए गए: भारत सरकार से कारीगर मामलों हेतु एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की औपचारिक अनुशंसा; राष्ट्रीय क्रिया परिषद के विस्तार एवं संचालन के साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेतृत्व की पुष्टि; राष्ट्रीय महिला कारीगर सशक्तिकरण प्रकोष्ठ का गठन; तथा राष्ट्रीय समिति से लेकर राज्य, जिला, नगर एवं ग्राम समितियों तक विस्तृत एक अस्थायी छह-माह की राष्ट्रीय संरचना को अंगीकार करना।

नेतृत्व की प्रतिक्रिया

> *"यह सम्मेलन भारत के कारीगर समुदायों की संस्थागत पहचान की दिशा में संगठित एवं साक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय कार्रवाई के अगले चरण की शुरुआत है। हम दान नहीं माँग रहे— हम वही समन्वित नीतिगत ध्यान माँग रहे हैं जो अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पहले से प्राप्त है।" — एडवोकेट ए. पद्मा चारी औसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्रिया परिषद*

> *"भारत के कारीगर कोई कल्याणकारी वर्ग नहीं, बल्कि एक उत्पादक राष्ट्रीय संपत्ति हैं। एक समर्पित मंत्रालय उस विखंडन को समाप्त करेगा जिसने दशकों से कारीगर विकास को सरकार में किसी एक जवाबदेह संस्था से वंचित रखा है।" — डॉ. वी. विश्वनाथन आचार्य, राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार, राष्ट्रीय क्रिया परिषद*

> *"हम दिल्ली से 2026-29 के राष्ट्रीय रोडमैप एवं 100-दिवसीय कार्ययोजना के साथ लौट रहे हैं — राज्य नेतृत्व चिन्हित हो चुका है, जिला मानचित्रण प्रगति पर है, और राष्ट्रीय सहभागिता डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यह आंदोलन भावना पर नहीं, संरचना पर आधारित है।" — प्रो. सागर झिलपे, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय क्रिया परिषद*

राष्ट्रीय विस्तार

सम्मेलन में केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा एवं दिल्ली के लिए राज्य अध्यक्षों की पुष्टि की गई। शेष राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को आगामी सप्ताहों में अपना नेतृत्व नामित करने हेतु आमंत्रित किया गया है। राज्य अध्यक्षों को दो सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय नेतृत्व एवं संगठनात्मक भागीदारों की पहचान करने का दायित्व सौंपा गया है।

आगे की राह

राष्ट्रीय सचिवालय शीघ्र ही नीति, विधिक मामले, सरकारी संबंध, महिला, युवा, प्रौद्योगिकी एवं डेटा, शोध तथा मीडिया — इन आठ राष्ट्रीय कार्यसमूहों हेतु परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आगामी 100 दिनों में परिषद कारीगर मामलों के मंत्रालय संबंधी श्वेत पत्र समिति का गठन, औपचारिक सरकारी सहभागिता ढाँचे की तैयारी, तथा भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिवों, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों, विधि विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों से युक्त राष्ट्रीय सलाहकार परिषद हेतु परामर्श आरंभ करने की योजना बना रही है।

आयोजकों ने इस सम्मेलन को एक रचनात्मक, साक्ष्य-आधारित एवं संस्था-निर्माण पहल बताया है, जो प्रकृति में पूर्णतः गैर-राजनीतिक है तथा कारीगर संगठनों, शोधकर्ताओं, नीति विशेषज्ञों, उद्योग एवं नागरिक समाज — सभी के लिए खुली है।

राष्ट्रीय क्रिया परिषद के बारे में

कारीगर मामलों के मंत्रालय की स्थापना हेतु राष्ट्रीय क्रिया परिषद (एनएसी) एक राष्ट्रीय समन्वय मंच है, जो भारत के कारीगर समुदायों की संस्थागत पहचान, नीतिगत समन्वय एवं साक्ष्य-आधारित विकास हेतु कार्यरत है। यह वंशानुगत एवं अन्य कारीगर विकास फाउंडेशन (वीएडीएफ), एक धारा 8 कंपनी, के प्रशासनिक एवं विधिक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करती है।

— समाप्त / ENDS —

मीडिया संपर्क: राष्ट्रीय सचिवालय, राष्ट्रीय क्रिया परिषद | karigar@artisansministry.com | pranaam@artisans.ngo | +91 96079 79893 | www.artisansministry.com